

प्रारंभिक परीक्षा

अरुल मिहु नवशक्ति विनयगर मंदिर

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की अपनी तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान अरुल मिहु नवशक्ति विनयगर मंदिर का दौरा किया।

अरुल मिहु नवशक्ति विनयगर मंदिर के बारे में

- सेशेल्स की राजधानी विकटोरिया में स्थित एक हिंदू मंदिर।
- यह देश का एकमात्र हिंदू मंदिर है।
- 1992 में हिंदू समुदाय द्वारा निर्मित, जो सेशेल्स की आबादी का लगभग 2% है।
- भगवान विनयगर (गणेश) को समर्पित और माहे (Mahé) द्वीप पर स्थित है।
- वास्तुकला
 - द्रविड़ शैली में डिजाइन किया गया है, जो तमिलनाडु और दक्षिण भारत के मंदिरों के समान है।
 - इसमें लगभग 100 फुट ऊंचा रंगीन गोपुरम है जो जटिल नक्काशीदार और चमकीले रंग के देवताओं और पौराणिक आकृतियों से सुशोभित है।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP)

संदर्भ

हाल ही में एक UNESCAP रिपोर्ट का अनुमान है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को लगभग 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त अंतर (gap) का सामना करना पड़ता है, जो जलवायु कार्रवाई में अधिक निवेश की आवश्यकता को उजागर करता है।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) के बारे में

- 1947 में स्थापित, यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे समावेशी अंतर-सरकारी मंच है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में से एक है।
- कार्य: सदस्य राज्यों और सहयोगी सदस्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
- सदस्यता: इसमें 53 सदस्य राज्य शामिल हैं।
- मुख्यालय: बैंकॉक, थाईलैंड।

संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय आयोग	कवर किया गया क्षेत्र	मुख्यालय
संयुक्त राष्ट्र यूरोप आर्थिक आयोग	यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया	जिनेवा, स्विट्जरलैंड
संयुक्त राष्ट्र अफ्रीका आर्थिक आयोग	अफ्रीका	अदीस अबाबा, इथियोपिया
संयुक्त राष्ट्र लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आर्थिक आयोग	लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	सैंटियागो, चिली
संयुक्त राष्ट्र पश्चिमी एशिया आर्थिक और सामाजिक आयोग	पश्चिमी एशिया (मध्य पूर्व)	बेरूत, लेबनान
संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग	एशिया और प्रशांत	बैंकॉक, थाईलैंड

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) का नवीनतम संस्करण जारी किया है, जिसमें भू-राजनीतिक विखंडन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तीव्र प्रगति को वैश्विक वित्तीय प्रणाली को नया आकार देने वाली प्रमुख ताकतों के रूप में रेखांकित किया गया है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में

- 2010 से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रकाशित एक व्यापक अर्धवार्षिक रिपोर्ट।
- यह भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, लचीलेपन और कमजोरियों का आकलन करती है, और बैंकों, बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) सहित प्रमुख वित्तीय क्षेत्रों के प्रदर्शन और सुदृढ़ता को कवर करती है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) 2026 के मुख्य बिंदु

- महत्वपूर्ण बाहरी झटकों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है।
- मजबूत आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं की स्वस्थ बैलेंस शीट और पर्याप्त पूंजी बफर ने वृहद-वित्तीय (macro-financial) स्थिरता बनाए रखने में मदद की है।
- रिपोर्ट उन प्रमुख कमजोरियों की पहचान करती है जो भविष्य के झटकों को बढ़ा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - उच्च सार्वजनिक ऋण,
 - बांड बाजारों में अस्थिरता,

- संपत्ति का बढ़ा हुआ मूल्यांकन

प्रो. पी.सी. महालनोबिस

संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारत की सांख्यिकीय प्रणाली में प्रो. पी.सी. महालनोबिस के योगदान को सम्मानित करने के लिए, उनकी 133वीं जयंती के अवसर पर 29 जून 2026 को 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया।

प्रो. पी.सी. महालनोबिस (1893–1972) के बारे में

- भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं।
- 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के संस्थापक; 1959 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।
- स्थापना की:
 - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) (1950)
 - केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)
 - सांख्य (Sankhya) (1933), भारत की पहली सांख्यिकीय पत्रिका।
- प्रथम योजना आयोग के सदस्य और महालनोबिस मॉडल के माध्यम से द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) के प्रमुख वास्तुकार, जिसने भारी औद्योगिकीकरण और पूंजीगत वस्तु उद्योगों पर जोर दिया।
- महालनोबिस दूरी (Mahalanobis Distance) (1930) विकसित की, जो मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन और बहुभिन्नरूपी विश्लेषण (multivariate analysis) में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक सांख्यिकीय उपाय है।
- बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण पद्धति का नेतृत्व किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए नमूने पूर्ण जनगणना की तुलना में बहुत कम लागत पर विश्वसनीय अनुमान उत्पन्न कर सकते हैं।
- 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में

- मनाया जाता है: 2007 से हर साल 29 जून को।
- उद्देश्य: प्रो. पी.सी. महालनोबिस की स्मृति में, सामाजिक-आर्थिक योजना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

बंगाल लोमड़ी (BENGAL FOX)

संदर्भ

शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों ने तमिलनाडु के कई जिलों में बंगाल लोमड़ी के देखे जाने में तेज गिरावट की सूचना दी है।

बंगाल लोमड़ी के बारे में

- इसे भारतीय लोमड़ी या भारतीय रेगिस्तानी लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक छोटा मांसाहारी स्तनपायी है।
- **आवास:** खुले घास के मैदानों, कांटेदार झाड़ियों, अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, तलहटी, और अन्य गैर-वन परिदृश्यों को तरजीह देती है।
- **वितरण:** भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी, जो भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती है।
- **व्यवहार:**
 - यह एक साथी के साथ रहने वाला (मोनोगैमस) जीव है, जिसमें जोड़े लंबे समय तक साथ रहते हैं।
 - इसने दिन में सक्रिय रहने के बजाय अब सुबह-शाम (crepuscular) और रात में सक्रिय रहने की आदत अपना ली है।
 - इसे 'एज स्पीशीज़' (edge species) माना जाता है, क्योंकि यह जंगल और खेती वाली ज़मीन के बीच के इलाकों में रहती है।
- **गर्भकाल:** 50–60 दिन।
- **संरक्षण की स्थिति:**
 - आईयूसीएन (IUCN): कम चिंताजनक (Least Concern)
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची II

मुख्य परीक्षा

संघीय राजकोषीय असंतुलन: राज्यों का बढ़ता ऋण बोझ

संदर्भ

केरल और तमिलनाडु द्वारा बढ़ते सार्वजनिक ऋण को उजागर करने वाले श्वेत पत्र (White Papers) जारी करने के बाद भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित हुआ है। इन रिपोर्टों ने इस बहस को फिर से प्रज्वलित कर दिया है कि क्या बढ़ता राज्य ऋण राजकोषीय कुप्रबंधन को दर्शाता है या राज्यों की विकास संबंधी जिम्मेदारियों और उनकी सीमित राजस्व-जुटाने की शक्तियों के बीच एक संरचनात्मक असंतुलन है।

बढ़ता राजकोषीय असंतुलन सहकारी संघवाद को कैसे कमजोर करता है?

- **कराधान शक्तियों का केंद्रीकरण:** जीएसटी (GST) की शुरुआत ने प्रमुख अप्रत्यक्ष कराधान शक्तियों को राज्यों से हटाकर एक सामान्य ढांचे में स्थानांतरित कर दिया, जिससे उनकी स्वतंत्र राजस्व-जुटाने की क्षमता कम हो गई।
 - **उदाहरण:** जीएसटी की शुरुआत के बाद राज्यों ने चुंगी (octroi), प्रवेश कर (entry tax) और कई स्थानीय शुल्कों जैसे करों को छोड़ दिया।
- **घटता प्रभावी कर हस्तांतरण (Tax Devolution):** उपकर (cesses) और अधिभार (surcharges) पर बढ़ती निर्भरता, जिन्हें विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर रखा गया है, ने राज्यों को हस्तांतरित होने वाले केंद्रीय करों के प्रभावी हिस्से को कम कर दिया है।
 - **उदाहरण:** यद्यपि 16वें वित्त आयोग ने 41% ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण को बरकरार रखा है, लेकिन गैर-साझा करने योग्य उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने राज्यों द्वारा प्राप्त वास्तविक राजस्व को कम कर दिया है।
- **केंद्रीय हस्तांतरण पर उच्च निर्भरता:** स्वयं के स्रोत से सीमित राजस्व कई राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान और हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर बनाता है।
 - **उदाहरण:** कुल राज्य राजस्व में केंद्रीय हस्तांतरण का हिस्सा 44% से अधिक है और बिहार में यह लगभग 72% है।
- **राजकोषीय स्वायत्तता का क्षरण:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की बढ़ती संख्या ने व्यय प्राथमिकताएँ निर्धारित करने में राज्यों के लचीलेपन को सीमित कर दिया है।
 - **उदाहरण:** स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में CSS के विस्तार ने संबंधित नीतिगत स्वायत्तता के बिना राज्यों के वित्तीय दायित्वों को बढ़ा दिया है।
- **राजकोषीय संघवाद में संस्थागत असंतुलन:** राजकोषीय संस्थानों में कथित विषमताओं ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।
 - **उदाहरण:** राज्यों ने वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंडों और जीएसटी परिषद के भीतर निर्णय लेने, विशेष रूप से कर प्रयास और जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में चिंता व्यक्त की है।

भारतीय राज्यों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **जनसांख्यिकीय-संचालित राजकोषीय दबाव:** राज्यों को अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण के आधार पर अलग-अलग व्यय आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके राजकोषीय संसाधनों पर निरंतर दबाव पड़ता है।
 - **उदाहरण:** बिहार जैसे युवा राज्यों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन में अधिक निवेश की आवश्यकता है, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे वृद्ध राज्यों को पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल पर बढ़ते खर्च का सामना करना पड़ता है।
- **सामाजिक क्षेत्र के खर्च पर राजकोषीय दबाव:** आवश्यक कल्याणकारी सेवाओं को प्रभावित किए बिना राजकोषीय गुंजाइश (fiscal space) बढ़ाने के लिए राज्यों के पास सीमित लचीलापन है।
 - **उदाहरण:** स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में कटौती मानव विकास संकेतकों में लंबे समय से हासिल किए गए लाभों को कमजोर कर सकती है।
- **स्वयं के राजस्व स्रोतों का कम उपयोग:** राज्यों ने उपलब्ध कराधान और गैर-कर राजस्व साधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, जिससे निजी संपत्ति बढ़ने के बावजूद उनकी राजकोषीय क्षमता सीमित हो गई है।
 - **उदाहरण:** कमजोर संपत्ति कर प्रशासन और सीमित भूमि मुद्रीकरण ने राजस्व को सीमित कर दिया है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के पास बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण के लिए अपर्याप्त संसाधन रह गए हैं।
- **उच्च ऋण सेवा बोझ (Debt Servicing Burden):** बढ़ते ब्याज दायित्व राज्य के वित्त के एक बड़े हिस्से की खपत करते हैं, जिससे विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश कम हो जाती है और ऋण का स्तर विवेकपूर्ण सीमाओं से परे चला जाता है।
 - **उदाहरण:** जैसा कि हाल ही में आरबीआई की राज्य वित्त रिपोर्टों में उजागर किया गया है, कई राज्य मौजूदा ऋण चुकाने के लिए राज्य विकास ऋण (SDLs) के माध्यम से नए उधार पर तेजी से निर्भर हैं, जिससे एक निरंतर ऋण चक्र बन रहा है।
- **उधार लेने की उच्च लागत:** बाजार-आधारित उधार पर निर्भरता बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण लागत बढ़ाती है।
 - **उदाहरण:** चीनी स्थानीय सरकारों के विपरीत, जो अक्सर कम लागत वाले घरेलू वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त करती हैं, भारतीय राज्य SDLs के माध्यम से अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरों पर उधार लेते हैं।
- **राज्य-स्तरीय राजकोषीय कुप्रबंधन:** लोकलुभावन खर्च, गैर-लक्षित सब्सिडी और बढ़ते प्रशासनिक व्यय ने कई राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया है।
 - **उदाहरण:** राज्य बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के बार-बार होने वाले वित्तीय संकट ने सरकारों को उदय (UDAY) योजना जैसे बार-बार बेलआउट उपाय करने के लिए मजबूर किया है, जिससे सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

- **संतुलित संघवाद के लिए राजकोषीय हस्तांतरण में सुधार:** सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करते हुए राज्यों के बीच राजकोषीय समानता को संतुलित करने के लिए वित्त आयोग के हस्तांतरण फार्मूले को संशोधित करना।
 - **उदाहरण:** बिहार जैसे राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों के लिए पुनर्वितरण सहायता जारी रखना, जबकि कर प्रयास, जनसंख्या स्थिरीकरण और राजकोषीय अनुशासन में उपलब्धियों के लिए केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रदान करना।
- **दीर्घकालिक विकास वित्त तक पहुंच का विस्तार:** राज्य सरकारों द्वारा घरेलू बचत को उत्पादक निवेश में लगाने के लिए तंत्र बनाना।
 - **उदाहरण:** राज्य विकास ऋण (SDLs) और अन्य राज्य-समर्थित बुनियादी ढांचा बांडों में अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करना।
- **राज्यों के लिए उधार लेने की लागत को कम करना:** समन्वित राजकोषीय सहायता और उन्नत ऋण तंत्र के माध्यम से राज्य के उधार पर ब्याज का बोझ कम करना।
 - **उदाहरण:** एक संघ-समर्थित 'क्रेडिट एन्हांसमेंट फ्रेमवर्क' SDLs पर ब्याज प्रीमियम को कम कर सकता है, जिससे विकास के लिए राजकोषीय गुंजाइश बढ़ सकती है।
- **पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को प्राथमिकता देना:** दीर्घकालिक विकास को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक व्यय को धीरे-धीरे बुनियादी ढांचे और उत्पादक परिसंपत्ति सृजन की ओर स्थानांतरित करना।
 - **उदाहरण:** परिवहन नेटवर्क, औद्योगिक गलियारों, अनुसंधान संस्थानों और प्रौद्योगिकी पार्कों में निवेश बढ़ाना।
- **राज्य स्तर पर राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करना:** अस्थिर राजस्व व्यय और लोकलुभावन उपायों पर उत्पादक पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिए राजकोषीय सुरक्षा उपायों को संस्थागत बनाना।
 - **उदाहरण:** प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले उनकी दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और ऋण निहितार्थ का आकलन करने के लिए स्वतंत्र राज्य राजकोषीय परिषदों की स्थापना करना।